

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास — श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2017

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

कुम्भाराम पुत्र दानाराम जाति
जाट निवासी भदवासी
तहसील व जिला नागौर।

1मूलाराम दत्तक पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी भदवासी तहसील
व जिला नागौर।
2तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल सुथार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.3.18

{1}-अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम भदवासी के बंटवाडा आदेश दिनांक 16.07.12 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 06.03.2017 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवाडा आदेश दिनांक 16.7.12 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं.1 ने गोदनामा की फोटोप्रति पेश की है।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने बहस शुरू करते हुए बताया कि

{2}{I}- अपीलाधीन बंटवाडा आदेश की जानकारी अपीलान्त को नहीं थी। अभी करीब 20-25 दिन पूर्व अपीलान्त ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से बंटवाडा करने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बंटवाडा पूर्व में ही करवा लेने का कहा जिस पर अपीलान्त ने रिकॉर्ड की नकले दिनांक 25.01.17 को प्राप्त की। तब बंटवाडा बात जानकारी हुई। तब अपीलान्त ने तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो नकले दिनांक 16.02.17 को तैयार होकर प्राप्त हुई तब अपीलान्त को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत रूप से अपना हिस्सा अधिक बताते दानाराम की सम्पत्ति में हक अधिकार नहीं होते हुए भी दानाराम की सम्पत्ति में अपना बंट बता कर दिनांक 16.07.12 को बंटवाडा करवा लिया। नकले प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये जानकारी से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिये जानकारी से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस मामले में भाईयों के बीच विवाद है। इसलिये गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को काल बाधित नहीं माना जाना चाहिये। अपीलान्त द्वारा आदेश जैर अपील की जानकारी होते ही अपील मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलान्त के आचरण में सुस्ती, लापरवाही अथवा दुराशय भी नहीं है तथा विलंब असामान्य नहीं होने से तकनीकी आधारों के बजाय मामले को गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिये। इसलिये अपील अंदर मियाद सुमार मानी जाना उचित व न्यायसंगत है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2015 पेज 592, आरआरटी 2015 (2) पेज 878, आरआरटी 2011 (1) पेज 602, डीएनजे (राज) 2014 (3) पेज 1136, आरआरटी 2006-07 (Supp) पेज 372, आरआरटी 2012 (1) पेज 668, आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, आरआरटी 2011 (2) पेज 829, आरआरटी 2008 (2) पेज 1183 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{2}{II}-म्यूटेशन जैर अपील खिलाफ कानून व उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}{III}-रेस्पोडेन्ट सं. 1 आज से करीब 45 वर्ष पहले ही रावतराम के गोद चला गया व दानाराम के जीवन काल में ही गोद चला गया व रावतराम का उत्तराधिकारी हो गया। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार



अपर कलक्टर, नागौर

अधिनियम के प्रावधानों व हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद जाने के दिन से ही दत्तक पुत्र का संबंध अपने जाइन्दा माता पिता से समाप्त हो जाता है व गोद के दिन से ही दत्तक पिता के उत्तराधिकार बाबत प्राकृतिक पुत्र के समान हक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं व जाइन्दा पिता के परिवार से संबंध समाप्त हो जाने के कारण जाइन्दा पिता की सम्पति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का संबंध आज से करीब 45 साल पहले ही दानाराम के परिवार से समाप्त हो गये व दत्तक पुत्र के रूप में रावतराम के उत्तराधिकार के प्राकृतिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिये दानाराम की सम्पति में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में दानाराम के खातेदारी के खेताय खसरा नं. 139, 140, 178 व 158/609 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है व खसरा नं. 38 व 39 में मात्र 1/2 हिस्सा बनता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 को खेताय खसरा नं. 139, 140, 178 व 158/609 का बंटवाडा करवाने का कोई अधिकार नहीं है व न ही उक्त खेताय में किसी प्रकार का हक हिस्सा ही बनता है व न ही प्राप्त करने का अधिकारी ही है। इसलिये विवादित म्यूटेशन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

[2](IV)—अपीलांट की माता अणदी का देहान्त दिनांक 03.01.09 को हो गया। जिसका एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलांट ही है। रेस्पोडेन्ट गोद हो जाने के कारण अपनी जाइन्दा माता का उत्तराधिकारी नहीं रहा। परंतु अणदी के फौतगी नामान्तरकरण में भी तत्कालीन पटवारी हल्का के साथ मिलावट कर अपना नाम उत्तराधिकारी नहीं होते हुए भी दर्ज करवा लिया व इसी आधार पर हिस्सा नहीं होते हुए भी व बंटवाडा करवाने का अधिकारी नहीं होते हुए भी मिलावट कर बंटवाडा करवा लिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

[2](V)—रेस्पोडेन्ट सं. 1 की नीयत अपने जाइन्दा पिता दानाराम की सम्पति में बिना अधिकार के हिस्सा प्राप्त करने व अपीलांट की सम्पति को हडपने की रही इसलिये अपीलांट के भोलेपन व जानकारी नहीं होने व अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को अपना बडा भाई मानकर किये जा रहे विश्वास का फायदा उठाकर उक्त दानाराम की खातेदारी के खेताय में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी दानाराम की फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। क्योंकि अपीलांट तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 पर पूर्ण विश्वास करता था। इसलिये खेतों की खातेदारी की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी की माता की देहान्त होने के बाद भी फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया व करीब 4 साल पहले रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने नाम से किसान कार्ड उठाने का कहरकर सहमति देने का कहा जिस पर अपीलांट ने सहमति देने का कह दिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्टांप पेपर पर लिखापढी कर खाली फार्म पर व लिखापढी बाबत जानकारी दिये बिना अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये व अपीलांट ने विश्वास कर अपने हस्ताक्षर बिना दस्तावेज को पढे कर दिये। उक्त दस्तावेज को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने काम में लेते हुए पटवारी हल्का के साथ मिलावट कर गलत रूप से अपीलांट के साथ धोखा करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा करवा लिया जो धोखा करते हुए कूट रचित रूप से बिना जानकारी दिये गलत रूप से हिस्से से अधिक बिना अधिकार के बंटवाडा अपने नाम करवाया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

[2](VI)—उक्त बंटवाडा तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार नागौर ने दोनों पक्षों के बयान नहीं लिये व न ही बंटवाडा बाबत तस्दीक की। यदि तस्दीक की जाती तो अपीलांट द्वारा वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जाते व वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जाते व वास्तविक हालात व गोद बाबत तथ्य प्रकट किये जाते जिससे बंटवाडा संभव नहीं था। संपूर्ण कार्यवाही मिलावट कर की गई है। इसलिये भी अपीलाधीन बंटवाडा आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2012 पेज 825 नजीर प्रस्तुत की। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट पर अत्यधिक विश्वास होने से आपसी राजनामा से बंटवाडा हुआ है। मगर रेस्पोडेन्ट का आराजी भूमि में हक हिस्सा नहीं होते हुए भी उसने विधिविरुद्ध बंटवाडा करवाया है। जो निरस्त कर वापस सुनवाई पर लिया जा सकता है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 2015 (2) पेज 1438 व डीएनजे (एससी) 2010 पेज 900 नजीर प्रस्तुत की गई है।

[3]—वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि



अपर कोर्ट, नागौर

[3](I)—वाद्ग्रस्त खेताय पैतृक खेताय थे, इनका आपसी सहमति से बंटवाडा की लिखत दिनांक 16.07.12 को अपीलांट व रेस्पोजेन्ट के बीच लिखी जाकर उसी दिन नोटेरी से तस्दीक कराया गया था व उसी रोज तहसीलदार नागौर को अपीलांट व रेस्पोजेन्ट ने वाद्ग्रस्त खेत का बंटवाडा हेतु आवेदन पेश किया था। जिस पर दोनो पक्षो को पूरी पूछताछ करके बंटवाडा किया गया था, उसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो रखा है। ऐसी देशा में अपीलांट का यह कथन कि दिनांक 25.01.17 को नकल लेने पर जानकारी हुई, कहना पूर्ण रूप से झूठ है तथा आदेश जैर अपील की जानकारी वक्त बंटवाडा वर्ष 2012 में हो जाना रिकार्डेड साबित हो जाने के बावजूद भी इतने विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। जो मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आदेश जैर अपील दिनांक 16.7.12 के विरुद्ध अपील करीबन 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। देरी का कारण भी सदभाविक नहीं है तथा निराधार व बनावटी है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में अंदर मियाद की अर्जी बनावटी व झूठी कहानी पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 488, आआरडी 2016 रामजीलाल बनाम रामजीलाल, आरआरटी 2015 (1) पेज 232, आरआरटी 2002 (1) पेज 77, आरआरडी 2003 पेज 416, आरआरटी 2012 (1) पेज 512 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

[3](II)—अपीलांट द्वारा रेस्पोजेन्ट मूलाराम का 45 वर्ष पूर्व गोद जाने का कथन किया। जबकि संवत् 2050 की आखातीज को गोदनामा हुआ है। जो गोदनामा दिनांक 05.01.94 को पंजीबद्ध है। उक्त गोद से पहले रेस्पोजेन्ट मूलाराम के जाईन्दा पिता का देहान्त हो चुका था। यानि पिता की सम्पति उसे उत्तराधिकार में स्व. मूलाराम से मिलनी थी। जो मिली है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि पक्षकारों में आपसी रजामंदी से बंटवाडा हुआ है तथा वो रिकार्डेड खातेदार भी रहे हैं तो ऐसी डिक्री को अब चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 1954 पेज 106, सीसीसी 1994 (2) पेज 514, आरआरडी 1970 पेज 21 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम भदवासी में स्थित भूमि खसरा नं. 139, 140, 178, 38, 39 व 158/609 की 82.01 बीघा भूमि का रिकार्डेड सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 16.7.12 को किया गया है। जो कूटरचित रूप से किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पर साबित नहीं है। अपील करीब 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नहीं है। अपीलांट 5 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहा हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नहीं है तथा वर्ष 2012 में इसी भूमि को लेकर दोनो पक्षो ने आपसी रजामंदी से भूमि का विभाजन करवाया है तो अब उसका यह कथन कि उसे आदेश जैर अपील की पूर्व में जानकारी नहीं हो, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)

अपर कलक्टर,
नागौर

